

केन्द्रीय सूचना आयोग
Central Information Commission
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
Baba Gangnath Marg, Munirka
नई दिल्ली, New Delhi – 110067

द्वितीय अपील संख्या / Second Appeal No. **CIC/MHOME/A/2022/625841**
CIC/MHOME/A/2022/122956

Shri Satwant Singh Yadav

... अपीलकर्ता /Appellant

VERSUS/बनाम

PIO

...प्रतिवादीगण /Respondent

PMA Cell

Director Police-I,

Ministry of Home Affairs

Date of Hearing : 19.04.2023

Date of Decision : 24.04.2023

Chief Information Commissioner : Shri Y. K. Sinha

Relevant facts emerging from appeal:

Since both the parties are same, the above mentioned cases are clubbed together for hearing and disposal.

Case No.	RTI Filed on	CPIO reply	First appeal	FAO	2 nd Appeal dated
625841	15.12.2021	12.01.2022	30.01.2022	22.02.2022	07.05.2022
122956	16.12.2021	12.01.2022	30.01.2022	22.02.2022	17.05.2022

Information sought and background of the case:

(1) CIC/MHOME/A/2022/625841

(2) CIC/MHOME/A/2022/122956

The Appellant filed an RTI application dated 15.12.2021 & 16.12.2021 which was responded to by the CPIO vide letter dated 12.01.2022 is as under:-

क्रम सं०	वांछित सूचनाएं	दी जाने वाली सूचना
1	वीरता पुरस्कार गैलेंट्री मेडल हेतु पात्रता मापदंड क्या है ?	प्रासंगिक प्रावधान राष्ट्रपति सचिवालय की अधिसूचना संख्या-3-प्रेज और 4-प्रेज दोनों दिनांक 01 मार्च, 1951 द्वारा अधिसूचित विधियों और नियमों में दिए गए हैं और यह गृह मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.nic.in पर उपलब्ध है।
2	सेंट्रल पुलिस अवार्ड (CAPC अगस्त 2021) की जिस मीटिंग में मेरे (सतवन्त सिंह यादव पूर्व सहायक कमांडेंट, 85 बटालियन सीआरपीएफ) द्वारा नक्सल विरोधी अभियान में सीने में से गोली पार हो जाने के पश्चात भी अदम्य साहस व नेतृत्व क्षमता के परिचय देने हेतु पुरस्कार प्रदान करने हेतु चर्चा की गई थी उसकी मिनट्स की एक कापी उपलब्ध करवाने का श्रम करे।	पदक प्रदान करने की प्रक्रिया के साथ-साथ समिति की कार्यवाही गोपनीय प्रकृति की है, आपके द्वारा मांगी गई सूचनाओं का खुलासा नहीं किया जा सकता है। ये सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 (1) (ज़) के तहत उपलब्ध नहीं करायी जा सकती है।

3	इस नक्सल विरोधी अभियान के दौरान मेरे द्वारा प्रदर्शित अतुलनीय बहादुरी (सीआरपीएफ द्वारा अनुशंसित) को किन मापदण्डों की पात्रता के अनुरूप गैलेंटी मेडल के योग्य नहीं पाया गया ।	
4	कमेटी के सामने प्रस्तुत किए गये साइटेसन व अन्य सभी दस्तावेज एवं साक्ष्यों विडियो रिकॉर्डिंग सहित की एक कॉपी उपलब्ध कारवाई जाए ।	पदक प्रदान करने की प्रक्रिया के साथ-साथ समिति की कार्यवाही गोपनीय प्रकृति की है, आपके द्वारी मांगी गई सूचनाओं का खुलासा नहीं किया जा सकता है । ये सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 (1) (झ) के तहत उपलब्ध नहीं करायी जा सकती है ।
5	कृपया गृह मंत्रालय के आईडी नोट No 11020/67/2020-PMA दिनांक 08/09/2021 की एक कॉपी तथा पुलिस महानिरीक्षक द्वारा गृह मंत्रालय को प्रेषित पत्र संख्या 85(i)/2009-Ops-3 dated 20/05/2020 की एक कॉपी उपलब्ध करवाएँ ।	गृह मंत्रालय के आईडी नोट No 11020/67/2020-PMA दिनांक 08/09/2021 की कॉपी संलग्न है तथा पुलिस महानिरीक्षक द्वारा गृह मंत्रालय को प्रेषित पत्र संख्या 85(i)/2009-Ops-3 dated 20/05/2020 की प्रति सूचना का अधिकार अधिनियम ,2005 की धारा 8 (1) (ज) के तहत उपलब्ध नहीं करायी जा सकती है ।
6	क्या यह मुद्दा अभी गैलेंटी मेडल हेतु पुनर्विचाराधीन है ?	नहीं ।

Dissatisfied with the response received from the CPIO, the Appellant filed a First Appeal dated 30.01.2022. The FAA/Jt. Secretary(P-I), MHA vide order dated 22.02.2022 upheld the reply of the CPIO.

Aggrieved and dissatisfied, the Appellant approached the Commission with the instant Second Appeal.

Facts emerging in Course of Hearing:

The Appellant participated in the hearing through video conference. He stated that information does not fall under any exemption clauses under Section 8 of RTI Act as he is seeking his own information in the instant RTI Application.

The Respondent represented by Shri D.K Ghosh, Under Secretary & CPIO (Police-I Div., MHA) and Shri Susanta Parida, Section Officer, participated in the hearing through video conference. He stated that a point-wise reply was furnished to the Appellant vide letter dated 12.01.2022.

On the Commission's query regarding invoking exemption clause under Section 8 (1) (i) of the RTI Act for point no. 2, 3 and 4 of the RTI Application, the Respondent could not provide a cogent reply.

Decision:

Upon perusal of the facts on record as well as on the basis of the proceedings during the hearing, the Commission observes that the CPIO has denied the

information to the Appellant under Section 8 (1) (i) of the RTI Act for point no. 2, 3 and 4 of the RTI Application, which is legally untenable.

The Commission further observes that denial of information under Section 8 (1) (j) of the RTI Act for point no. 5 of the RTI Application is not found legally convincing. Therefore, the Commission directs the CPIO to provide a revised reply qua the query number 5 of the instant RTI Application, either justifying the denial of information under Section 8(1)(j) of the RTI Act, or furnish the information sought by the Appellant, invoking the severability clause under Section 10 of the RTI Act, to redact all personal information related to any third party. The Respondent shall submit a compliance report before the Commission in this regard with necessary proof of service send this revised reply to the Appellant, with a copy marked to the Commission, within two weeks from the date of receipt of this order.

With the above observations, the instant Second Appeals stand disposed off.

Y. K. Sinha (वाई. के. सिन्हा)

Chief Information Commissioner (मुख्य सूचना आयुक्त)

Authenticated true copy
(अभिप्रमाणित सत्यापित प्रति)

S. K. Chitkara (एस. के. चिटकारा)
Dy. Registrar (उप-पंजीयक)
011-26186535